www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 311 | जौनपुर गुरुवार, 02 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक हुआ प्रदर्शन

जयपुर, (एजेंसी)। बुधवार शाम जयपुर में खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश (डीएनटी) समुदायों की महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सभा के बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोका, तो स्थिति हिंसा में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे।हिंसा में पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, और अधिकारियों ने बताया कि बाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई। लगभग 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश समुदायों के सदस्य 10 प्रतिशत आरक्षण की अपनी मांग को लेकर विद्याधर नगर स्टेडियम में एक महापंचायत के लिए एकत्रित हुए थे।शाम करीब 6 बजे बैठक समाप्त होने के बाद, प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने की घोषणा की। पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी और बैरिकेड लगा दिए थे। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, तो झड़प शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक रूप ले गई।

दिल्ली में होने वाले विरोध–प्रदर्शन से पहले कैबिनेट में फेरबदल करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के जंतर–मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध–प्रदर्शन से पहले वह अपनी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू–कश्मीर में दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं।राजनीति उन्होंने कहा कि एनसी जम्मू–कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर एक अहम बैठक करेगी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, ताकि जंतर–मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके और यह तय किया जा सके कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन होने वाले प्रदर्शन में कौन से नेता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

जापान की प्रीसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा : पीएम मोदी

जापान, (एजेंसी)। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ जॉइंट प्रेस वक्तव्य के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की प्रीसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को–डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। भारत और जापान की निवेशक के तौर पर साझेदारी निरंतर सुदृढ हो रही है। पिछले 1 वर्ष में करीब 120 नए व्यावसायिक समझौते हुए हैं, जिनसे भारत में 10 बिलियन डॉलर से अधिक जापानी निवेश आएगा। पीएम मोदी ने कहा, "भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की पहली भारत यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं३वे जापान की नारा प्रीफेक्चर से आती हैं जो भारत–जापान के सांचा बौद्ध विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है।" पीएम मोदी ने कहा, "कुछ ही दिन पहले जी7 समिट में मैंने कहा था, कि वैश्विक उथल–पुथल के आज के माहौल में, आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटीजिक एसेट है। उन्होंने कहा, " मुझे गर्व है, कि भारत–जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में, इलेक्ट्रानिक्स तक, जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्रधानमंत्री ताकाइची की यात्रा से, हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटीजिक एण्ड ग्लोबल पार्टनर्शिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत और जापान, दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं।

दक्षिणी वायु कमान के नए प्रमुख बने एयर मार्शल जसवीर सिंह मान

, (एजेंसी)। अति विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना पदक से सम्मानित एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 1 जुलाई, 2026 को दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ (एओसी–इन–सी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 16 दिसंबर 1989 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त करने वाले एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर एयर कमांड और ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से अध्ययन किया है। वे पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर हैं और अपाचे, मिग–21, जगुआर, मिग–29, एसयू–30 तथा राफेल सहित विभिन्न लड़ाकू विमानों पर 3,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव रखते हैं। लगभग चार दशकों के सैन्य करियर में एयर मार्शल मान ने एक फाइटर स्क्वाड्रन और एक प्रमुख फाइटर एयरबेस की कमान संभाली है। उन्होंने एयर डिफेंस कमांडर और एक कमांड में प्रशासनिक प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वायु मुख्यालय में उन्होंने सहायक वायु स्टाफ प्रमुख (ऑपरेशंस–ऑफेंसिव) और महानिदेशक (वेपन सिस्टम्स) की जिम्मेदारी भी निभाई। अपनी नई नियुक्ति से पहले एयर मार्शल जसवीर सिंह मान पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परिचालन क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लिया है, जो 30 जून, 2026 को लगभग चार दशकों की गौरवशाली सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। एयर मार्शल मनीष खन्ना को उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय, एनईपी के विजन के अनुरूप राज्य में शिक्षा को फिर से बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से रोडमैप तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और पश्चिम बंगाल सरकार के ही स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन के साथ विस्तृत चर्चा की। यह चर्चा राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, विस्तार और निधि आवंटन पर केंद्रित थी,

जिसमें समग्र शिक्षा कार्यक्रम, पीएम–ऊषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान), पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) और उल्लास दृ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीएम स्कूलों के नेटवर्क का विस्तार उन ब्लॉकों तक किया जाए जो वर्तमान में इसके अंतर्गत शामिल नहीं हैं, और साथ ही इन्हें शहरी स्थानीय निकायों में भी विस्तारित किया जाए।

यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आई है. लगातार सातवें साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे. इस आशय की जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद् के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी है. उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. लगातार सातवें साल राज्य में बिजली बिल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद् के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस संदर्भ में एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि देश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश में सातवें साल भी नहीं बढ़ी.बिजली दर यथावत रहेगी. नोएडा पावर कंपनी में 10:छूट लागू रहेगी. वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद् की लड़ाई रंग लाई. उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत निगम चोर दरवाजे से बिजली के रेट्स बढ़ाना चाहता था लेकिन विद्युत नियामक आयोग के ऐलान से आज उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां सात साल से दाम नहीं बढ़े. अब आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन है, जहां पर दिन में ई रिक्शा या ईवी चार्जिंग करेगा, उसमें 20 फीसदी की छूट मिलेगी. हालांकि यह छूट केवल दिन में रहेगी। नियामक आयोग का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बीते दिनों बिजली उपभोक्ताओं पर सरचार्ज का बोझ पहले लादा गया फिर हटा लिया गया। इस संदर्भ में उर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का एक पत्र भी सामने आया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन को फटकार लगाई थी कि बिना उनसे चर्चा किए सरचार्ज का ऐलान कैसे कर दिया गया।

भारत-जापान व्यापार और निवेश को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध - पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि निवेश भारत–जापान साझेदारी का अहम आधार है और इसी के जरिए दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। 'द इंडो–जापान पीयूष गोयल ने कहा, "मारुति सुजुकी लगभग 40 साल पहले भारत आई और आधुनिक, किफायती तथा टेक्नोलॉजी आधारित गाड़ियां लेकर आई, जिसने भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनने की राह पर आगे बढ़ाया।" उन्होंने बताया कि मई महीने में भारत में बिकी 4 लाख पैसेंजर गाड़ियों में से 1.47 लाख मारुति सुजुकी की थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का पहला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओडिशा में जापान की साझेदारी से बनाया गया, जिससे लौह अयस्क के परिवहन को गति मिली। उन्होंने कहा कि भारत–जापान व्यापार केवल

आयात–निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच तकनीक और निवेश का मजबूत रिश्ता भी विकसित हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा, "हम कच्चा माल या इंटरमीडिएट उत्पाद नहीं बेच रहे हैं। हम जापान को उच्च गुणवत्ता वाले, सटीक इंजीनियरिंग वाले उत्पाद, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का निर्यात कर रहे हैं। इसलिए इस रिश्ते में व्यापार और निवेश दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं।" उन्होंने कहा कि भारत जापान के साथ व्यापारिक और निवेश साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। भारत–जापान की प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं में 508 किलोमीटर लंबा मुंबई–अहमदाबाद हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है। जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित इस परियोजना में ट्रेनें 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय छह घंटे से अधिक से घटकर करीब दो घंटे रह जाएगा। परियोजना में हुई देरी पर पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण में राजनीतिक कारणों से देरी की गई।

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, प्रधानमंत्री से पूछे कई सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि कथित तौर पर चोरी का पैसा प्रधानमंत्री तक पहुंचा, लेकिन उनका आरोप है कि पूरे मामले में दोषियों को बचाने और मामले को दबाने की कोशिश की गई।केजरीवाल ने कहा कि यदि इतने लंबे समय तक कथित अनियमितताएं होती रहीं तो संबंधित जिम्मेदार लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग भी उठाई।उन्होंने कहा कि अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वे निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जबकि पूरे मामले में बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री तक धन पहुंचने संबंधी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उनके पास नहीं है और इस विषय पर वे कोई निश्चित दावा नहीं कर रहे हैं।इसके अलावा उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य में कथित कमीशनखोरी के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि यदि निर्माण प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज हटाने और अन्य मामलों की समय रहते जानकारी संबंधित एजेंसियों को क्यों नहीं मिली।

आंध्र प्रदेश हरित ऊर्जा उत्पादन में अन्य राज्यों से आगे – मुख्यमंत्री नायडू

तिरुपति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश हरित ऊर्जा उत्पादन में अन्य राज्यों से एक कदम आगे है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में 160 गीगावाट बिजली उत्पादन की योजना बनाई है और 100 गीगावाट के लिए पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। वे तिरुपति जिले के सत्यवेदु के मदनपालम में हीरो मोटोकॉर्प के श्ग्लोबल पार्ट्स सेंटर 2.0श की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे।उन्होंने दावा किया कि सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी निर्णय ले रही है और वर्तमान में श्स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेसश प्रोटोकॉल लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई संपर्क की सुविधा है। हमने कृषि के साथ–साथ उद्योगों के लिए जल आपूर्ति के उपाय शुरू किए हैं। हम किसानों को राज्य के निरंतर विकास में भागीदार बना रहे हैं।नायडू ने कहा कि केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करने से आगे बढ़कर, सरकार उद्योगों को उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उद्योगों को आवश्यक सभी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएंगे। गूगल और अन्य जैसी कंपनियां विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर स्थापित कर रही हैं, ।

राम मंदिर मामले में दोषी को बचाने की कोशिश कर रही एसआईटी– अजय राय

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या यात्रा से पहले नजरबंद करने, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच, मंदिर प्रबंधन, उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान की पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों और उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी। अयोध्या यात्रा के दौरान हाउस अरेस्ट किए जाने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि इनकी जो चोरी का जो प्रकरण है, उसको पूरी तरीके से दबाना चाहते हैं, उसको ढकना चाहते हैं। इस नाते हम लोगों को दर्शन करने नहीं दिया। हम भगवान श्रीराम का दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आप रोक देंगे? इससे साबित होता है कि वहां पर जितने भी लोग व्यवस्था में लगे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके

से दोषी हैं और उस मामले को दबाने के लिए ये रोक रहे थे, लेकिन हमलोगों ने दर्शन किए। इनकी जो चोरियां हैं, वो सब सामने आ गईं। वहां के लोग मुंह खोलकर बोल रहे हैं कि इन्होंने चढ़वा चोरी में जबरदस्त चोरी किया है।राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह पहले से शंका थी कि एसआईटी जो जांच कर रही है, एसआईटी में जो अधिकारी हैं, विजय विश्वास पंत जो चेयरमैन हैं, वह प्रयागराज के भगदड़ में मुख्य व्यक्ति है। महाकुंभ में जब स्नान प्रारंभ हुआ था, उस दिन उस व्यक्ति ने सुबह ही कहा था कि श्उठो, उठो, सवेरा हो गया, जो सो रहा है वह खो रहा है, अमृत वर्षा हो रही है, पहुंचो।श उसके बाद भगदड़ हुई। विजय विश्वास पंत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और सरकार जो चाहेगी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। एसआईटी की जांच का कोई अर्थ ही नहीं है। उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से समयबद्ध जांच कराई जाए, जिससे समयबद्ध तरीके से चीजें आ सकें।

संपादकीय

एल नीन्यो का उभार

इस बार मॉनसून कमजोर रहने की आशंका है। इस चुनौती के मद्देझनर सरकार ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं, इस बारे में उसे देश को भरोसे में लेना चाहिए, ताकि लोग घबराहट से बच सकें। मौसम को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। आधा जून गुजर चुका है और अटके मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी बारिश में अब तक 35 प्रतिशत की कमी दर्ज हो चुकी है। वैसे इस समय तक ऐसा होना असामान्य नहीं है, मगर चिंता बढ़ाने वाला पहलू एन नीन्यो परिघटना का सक्रिय हो जाना है। अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वातावरणीय प्रशासन (एनओएए) ने 11 जून को एलान कर दिया कि भू–मध्यरेखा के पास प्रशांत महासागर में एल नीन्यो का उभार हो चुका है। एल नीन्यो प्रशांत महासागर में होने वाले उस बदलाव को कहते हैं, जिससे समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ता है और भारत में अक्सर सूखा या कम बारिश होती है। 1951 के बाद से 17 बार एन नीन्यो का उभार हुआ है, उनमें से 12 बार भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। एनओएए ने 1951 के बाद 17 में छह एन नीन्यो को श्अति शक्तिशालीय श्रेणी में रखा है। उसने कहा है कि इस बार का एन नीन्यो के भी श्अति शक्तिशालीय होने की संभावना है। भारत में धान, दलहन, और सब्जियों की खेती मानसूनी बारिश पर काफी हद तक निर्भर रहती है। कम बारिश होने पर डेयरी क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इसके अलावा भू–जल के स्वस्थ स्तर के लिए भी पर्याप्त बारिश अनिवार्य है। कम बारिश होने का पनबिजली परियोजनाओं पर भी खराब असर होता है। इसलिए बन रही स्थिति को लेकर एहतियाती कदम उठाने की अवश्यकता है। भारत के मौसम विभाग ने सामान्य की तुलना में 90 फीसदी तक ही बारिश होने का अनुमान लगाया है। लेकिन संभव है कि यह उससे भी कम हो। और ये चुनौती उस समय आई है, जब ईरान युद्ध के कारण उर्वरकों के अभाव और महंगाई की समस्या पहले से मंडरा रही है। इसलिए ये सवाल अहम है कि इन चनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं? इस बारे में उसे देश को भरोसे में लेना चाहिए, ताकि लोग घबराहट से बच सकें।

डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष : डिजिटल क्रांति से सशक्त हुआ भारत

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2026 को अपने 11 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2015 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी पहल ने भारत में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन–देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के तरीके में व्यापक बदलाव किया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) तंत्रों में से एक विकसित कर चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास, बैंकिंग और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक सुनिश्चित हुई है। डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज, सरल और नागरिक–केंद्रित बनाया है। पहले जहां सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारें, कागजी प्रक्रिया और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। डिजिटल अवसंरचना में निवेश के कारण गांवों से लेकर शहरों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और किफायती इंटरनेट ने डिजिटल तकनीक को आम नागरिक तक पहुंचाया है। पिछले एक दशक में भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है। एकीकृत भुगतान अंतरफलक (यूपीआई) के माध्यम से विश्व के लगभग 49 प्रतिशत रियल–टाइम डिजिटल भुगतान हो रहे हैं। देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 12 से 14 प्रतिशत का योगदान दे रही है, जिसके अगले दशक में लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नौ प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य डिजिटल पहुंच, सुशासन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। भारतनेट परियोजना के तहत जनवरी 2026 तक लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। लगभग सात लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई–शासन, ऑनलाइन शिक्षा, टेली–चिकित्सा और डिजिटल भुगतान को गति मिली है। मार्च 2026 तक देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 106.58 करोड़ हो गई है, जिससे अंतिम छोर तक डिजिटल संपर्क मजबूत हुआ है। देशभर में 6.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र तथा 1.6 लाख डाकघर डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, प्रमाण–पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य नागरिक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। डिजिटल लॉकर तथा राष्ट्रीय एकल साइन–ऑन प्रणाली जैसे मंचों के माध्यम से प्रमाण–पत्र, आवेदन, भुगतान और सरकारी सेवाएं अब कागजरहित और सरल हो गई हैं। ई–अस्पताल, ई–संजीवनी और ई–न्यायालय जैसी सेवाओं ने स्वास्थ्य एवं न्याय व्यवस्था को डिजिटल बनाया है। ई–न्यायालय परियोजना के तहत 660 करोड़ से अधिक पृष्ठ डिजिटल रूप में परिवर्तित किए जा चुके हैं तथा 1.07 करोड़ मामलों की ऑनलाइन दाखिल प्रक्रिया पूरी हुई है। माईगव और मुक्त सरकारी आंकड़ा मंच के माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं सूचनाओं तक वास्तविक समय में पहुंच मिल रही है। वर्ष 2014–15 में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 1.9 लाख करोड़ रुपये था, वहीं मार्च 2026 तक यह बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग ने वर्ष 2025 में 283 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया। देश में 2,100 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों में लगभग 26 लाख पेशेवर कार्यरत हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति, सुरक्षित सरकारी ई–मेल, सार्वजनिक वाई–फाई, डिजिटल पुस्तकें और संदेश आधारित मौसम चेतावनी जैसी पहलों ने डिजिटल शासन को मजबूत किया। जन–धन खाते, आधार और मोबाइल संपर्क ने वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया है। फरवरी 2026 तक जन–धन खातों की संख्या बढ़कर 57.78 करोड़ हो गई, जबकि आधार नामांकन 144 करोड़ से अधिक पहुंच गया। जून 2026 तक 176 करोड़ लाभार्थियों को 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। आधार ने सुरक्षित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक करोड़ों लोगों की पहुंच आसान बनाई। 30 अप्रैल 2025 तक 2,393 करोड़ से अधिक ई–केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक सत्यापन) लेन–देन दर्ज किए गए। आधार अनुप्रयोग के नवीन संस्करण को पांच माह में ही 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया।

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के शांति दूतों का सूख रहा है

नीरज

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के कथित लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरह बौखला गए हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उनके अस्तित्व पर हमला कर दिया है। देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू–कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है। साथ ही

सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं। इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पार से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी बेचौनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है? ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है। आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा। सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की हालत देखें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना तथा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही हैं। देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वालों को अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान यदि वास्तव में शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्टरी बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी। बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

हम विकास और विनाश के बीच संतुलन साध पाएंगे

ललित

वेनेजुएला में हाल में आए भीषण भूकम्प ने केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन त्रासदी की भयावहता निर्विवाद है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खोने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पूरी दुनिया संवेदना व्यक्त करती है, राहत सामग्री भेजती है, सहायता अभियान चलाती है, लेकिन एक प्रश्न बार–बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है–क्या हम हर बड़ी आपदा से कोई स्थायी सबक सीखते हैं या फिर कुछ दिनों की चर्चा और शोक के बाद सब कुछ भुलाकर पुनः उसी लापरवाह विकास–यात्रा एवं प्रकृति की घोर उपेक्षा पर निकल पड़ते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कभी कैलेंडर देखकर नहीं आतीं। वे न देश चुनती हैं, न मौसम और न समय। जब धरती कांपती है, नदियां उफान पर आती हैं, पहाड़ दरकते हैं या समुद्र विकराल रूप धारण कर लेता है, तब विकास के बड़े–बड़े दावे, ऊंची–ऊंची इमारतें और तकनीकी उपलब्धियों का अहंकार कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता है। ऐसे समय में किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि उसकी पूर्व तैयारी, संवेदनशील शासन व्यवस्था और जागरूक नागरिक होते हैं। वेनेजुएला की त्रासदी ने एक सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। आधुनिक तकनीक ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को भूकम्प के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी। सुनने में यह समय बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन आपदा की घड़ी में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। विज्ञान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक व्यापक बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। भारत के लिए यह विषय केवल एक अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है। हमारा देश स्वयं भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, चक्रवात और सुनामी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। 1993 का लातूर भूकम्प, 2001 का भुज भूकम्प, 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2023 की जोशीमठ भू–धंसाव की घटनाएं तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है–प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिक आज भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस दिन, किस समय और किस स्थान पर भूकम्प आएगा, लेकिन वे वर्षों से यह चेतावनी अवश्य देते रहे हैं कि भारत का लगभग साठ प्रतिशत भूभाग किसी न किसी स्तर के भूकम्पीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली–एनसीआर, उत्तर–पूर्व, गुजरात और अनेक अन्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि भूकम्प की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो भी पूर्व तैयारी पूरी तरह संभव है। दुर्भाग्य यह है कि हम तैयारी की अपेक्षा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देते हैं। आज देश के लगभग हर शहर में कंक्रीट के विशाल जंगल तेजी से खड़े हो रहे हैं। बहुमंजिला आवासीय परिसर, व्यावसायिक भवन, गगनचुंबी टावर और स्मार्ट सिटी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अब जयपुर जैसे शहर भी ऊंची–ऊंची इमारतों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन भवनों की मजबूती केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भी? किसी भी भवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धरती कांपती है, जब अचानक बाढ़ आती है, जब तेज हवाएं चलती हैं या जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यदि उस समय भवन लोगों की जान बचा सके, तभी उसे वास्तविक विकास का प्रतीक माना जाना चाहिए। केवल ऊंचाई, चमक–दमक और आधुनिक सुविधाएं किसी भवन को सुरक्षित नहीं बनातीं। भारत में भूकम्परोधी निर्माण के लिए मानक और नियम मौजूद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि उनके अनुपालन की है। क्या प्रत्येक बहुमंजिला इमारत वास्तव में उन्हीं मानकों के अनुरूप निर्मित हो रही है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होती है? क्या निर्माण के बाद संरचनात्मक सुरक्षा का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, तो चिंता स्वाभाविक है। निर्माण क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। अनेक बार भू–माफिया, बिल्डर लॉबी और लाभ–लोलुप तत्व पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए हरित क्षेत्रों, जलाशयों, नदी तटों और भू–संवेदनशील क्षेत्रों तक में निर्माण कर देते हैं। बाद में यही निर्माण किसी त्रासदी का कारण बनते हैं। नोएडा में अवैध रूप से निर्मित सुपरटेक ट्विन टावरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध था, तो उसे बनने की अनुमति किसने दी? निर्माण पूरा होने तक प्रशासन मौन क्यों रहा? क्या विकास के नाम पर कुछ लोगों के आर्थिक लाभ के लिए लाखों नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला जा सकता है? यह केवल कानूनी प्रश्न नहीं, बल्कि नैतिक प्रश्न भी है। शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर विकास न्यासों तथा भवन निर्माण की अनुमति देने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल नक्शों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हो सकती। प्रत्येक निर्माण की तकनीकी, पर्यावरणीय और संरचनात्मक जांच अत्यंत कठोरता से की जानी चाहिए। सुरक्षा मानकों का पालन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा का दायित्व है। एक अन्य गंभीर चिंता जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की है। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करना, जंगलों का अंधाधुंध विनाश, अतिक्रमण, खनन और अनियोजित शहरीकरण ने प्रकृति के संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप भूस्खलन, अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बार–बार आने वाली त्रासदियां हमें चेतावनी दे रही हैं कि विकास का मॉडल प्रकृति–विरोधी नहीं, बल्कि प्रकृति–संगत होना चाहिए। यह मान लेना भी खतरनाक है कि जिस क्षेत्र में पहले कभी बड़ा भूकम्प नहीं आया, वहां भविष्य में भी खतरा नहीं होगा। धरती के भीतर क्या हलचल चल रही है, इसका पूरा रहस्य आज भी मानव नहीं जान पाया है। इसलिए केवल पुराने अनुभवों के आधार पर किसी क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित मान लेना आत्मघाती हो सकता है। आज भवन निर्माण केवल भूकम्प को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता। अत्यधिक वर्षा, शहरी बाढ़, तेज हवाएं, तापमान में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों को भी नगर नियोजन का हिस्सा बनाना होगा। भविष्य के शहरों को बहुस्तरीय सुरक्षा की अवधारणा के आधार पर विकसित करना समय की मांग है।

सरल, सादगी और संवेदनशीलता के साथ विकास यात्रा का सशक्त नेतृत्व

तेजबहादुर सिंह भुवाल

किसान परिवार से निकलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सरल व्यक्तित्व, विनम्र व्यवहार और जनसेवा की भावना से जनता के बीच एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री साय का सार्वजनिक जीवन सादगी, जनसेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, वनवासियों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों की समस्याओं को निकट से समझा और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सत्ता के शीर्ष पद पर होने के बावजूद उनकी सादगी और सहजता आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री साय आम जनता से सीधे संवाद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। जनदर्शन, सुशासन तिहार और विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से वे स्वयं लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए त्वरित पहल करते हैं। बुजुर्गों के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्परता उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान है। आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री साय अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं। गांवों में बैठकर लोगों से चर्चा करना, उनकी समस्याओं को समझना और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनकल्याण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, अधोसंरचना, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 8,200 करोड़ रूपये का बजट महतारी वंदन योजना के लिए आवंटित किया है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं। राज्य सरकार ने धान खरीदी को प्राथमिकता देते हुए किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित की तथा लाखों किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाया। प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल करते हुए लाखों आवासों को स्वीकृति प्रदान की। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तेज गति से चल रहे निर्माण कार्यों के चलते प्रदेश में लाखों जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। बस्तर के जंगलों में उत्पादित होने वाले तेंदूपत्ता, आदिवासी समाज की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसी तेंदूपत्ता के सहारे हजारों गांवों में गर्मियों के महीनों में रोजगार मिलता है। इस काम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं, जिससे परिवार की कुल आय में संतुलन बनता है। यही वजह है कि तेंदूपत्ता संग्रहण को सरकार ग्रामीण रोजगार का मजबूत जरिया मानती है। राज्य सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बड़ी रहत देते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर में अहम बदलाव किया है। पूर्व में मिलने वाली राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये किया है। यह बढ़ोतरी सीधे–सीधे संग्राहकों लाभ पहुंचा रही है। जानकारों के अनुसार पहले बढ़ती महंगाई के मुकाबले संग्रहण की दर कम पड़ रही थी, लेकिन नई दर से मजदूरी और मेहनत का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुरक्षा के साथ–साथ संवेदनशील पुनर्वास और विकास पर भी समान रूप से कार्य कर रही है। नक्सली सरेंडर, विक्टिम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी–2025 के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर तथा आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक और मुख्यधारा से जुड़ा जीवन प्रदान किया जा रहा है। एक नवंबर 2024 से लागू छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024–30 राज्य को निवेश और उद्योगों के लिए नई पहचान दे रही है। न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के सिद्धांत पर आधारित यह नीति उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और निवेशक–अनुकूल बनाती है। व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन, समयबद्ध स्वीकृति और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इससे उद्यमियों को कम समय में आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त हो रही हैं और कारोबार करने में सुगमता बढ़ी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मजबूत और आधुनिक परिवहन नेटवर्क के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में रेल, सड़क और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे उद्योग, व्यापार, पर्यटन और आम नागरिकों की आवाजाही पहले से अधिक सुगम हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का निरंतर उन्नयन, नई सड़कों और पुलों का निर्माण तथा दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के प्रयासों ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई गति दी है। इससे माल परिवहन की लागत और समय में कमी आई है, जिससे उद्योगों और निवेशकों को सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य शासन की पहल से रेल नेटवर्क के विस्तार और नई रेल परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों, खनिज संपदा वाले इलाकों और प्रमुख शहरों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, हवाई सेवाओं के विस्तार, नए एयर रूट और बेहतर विमानन सुविधाओं से राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और भी मजबूत हुई है। बेहतर परिवहन अवसंरचना के कारण छत्तीसगढ़ आज निवेश, व्यापार और पर्यटन के लिए अधिक आकर्षक बन रहा है। यह मजबूत कनेक्टिविटी राज्य के समग्र आर्थिक विकास को नई दिशा देने के साथ–साथ रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर भी सृजित कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर रुख अपनाते हुए प्रशासनिक जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। योजनाओं में लापरवाही और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को शासन की आधारशिला बनाया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जन–केंद्रित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित जांच, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई, तथा अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी को तकनीक आधारित बनाया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों मजबूत हुई हैं। इसके लिए ई–ऑफिस, सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ई–गवर्नेंस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाया गया है।

चिकित्सक केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता के जीवंत प्रतीक हैं –सीएमओ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लायंस क्लब जौनपुर श्गोमतीश् द्वारा चिकित्सक दिवस के अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित होटल में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीएमओ को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित किया गया।। डॉ. गंगाराम गौतम ने कहा कि चिकित्सक केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता के जीवंत प्रतीक हैं। समाज के प्रति उनके योगदान को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है।समाज में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से योगदान दे रहे चिकित्सकों को सम्मानित करके क्लब ने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। देश व प्रदेश की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवा का लाभ हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे उसकी जरूरत है।इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड के जरिए पाँच लाख तक स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया जा रहा है देश मे करोड़ो परिवार को इसका लाभ मिल रहा।जिले के कई प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल से गरीब परिवार के लोग इसका लाभ उठा रहे है। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा समारोह में आई एम ए की अध्यक्षा डॉ. शुभा सिंह, डॉ. अरुण कुमार मिश्रा, डॉ. रामअवध यादव, डॉ. शकुंतला यादव, डॉ. जी. सी. सिंह, डॉ. सुलोचना सिंह , डॉ. वीणा त्रिपाठी, डॉ. विवेक श्रीवास्तव, डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव डॉ. मिर्जा मोहम्मद मेहर अब्बास, नीमा के अध्यक्ष डॉ. डी. सी. मौर्या, डॉ. आलोक यादव, डॉ. रॉबिन सिंह, डॉ. सबा, डॉ. सज्जाद मेहदी, डॉ. श्रवण यादव, डॉ. राजेश मौर्य, डॉ. रश्मि मौर्य, डॉ. नरेन्द्र यादव, डॉ. पूजा यादव, सहित नगर के अनेक प्रतिष्ठित चिकित्सक उपस्थित रहे। क्लब की ओर से सभी चिकित्सकों को माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति–चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष सै. हसनैन कमर श्दीपूश् ने की। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का सम्मान समाज के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्लब के सचिव लायन नवीन मिश्रा प्रज्ञा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मनीष गुप्ता, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गर्वनर प्रतिमा गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष देवेश गुप्ता, धनंजय पाठक, ध र्मेंद्र गुप्ता, धीरज गुप्ता, मनीष गुप्ता, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गर्वनर प्रतिमा गुप्ता, मौर्या,एमजेएफ दीपक चिटकारिया, वीरेन्द्र कुमार सिंह, संतोष साहू, गणेश गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, अनिल कुमार पाण्डेय, अनिल अग्रहरि, ओमित साहू, सुनील गुप्ता, खुशबू गुप्ता, सुधा मौर्या,खुशबू जायसवाल, संयोजक गौरव श्रीवास्तव, मुकेश मौर्य, सहित क्लब के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अंत में क्लब के कोषाध्यक्ष ऋषिदेव ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों, पत्रकारों और सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। पूरे समारोह का वातावरण सेवा, सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से ओत–प्रोत रहा तथा कार्यक्रम ने उपस्थित सभी लोगों पर अपनी विशेष छाप छोड़ी है।

जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा–2026 के सकुशल, निष्पक्ष एवं नकलविहीन आयोजन के दृष्टिगत जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने आज टी.डी. लॉ कॉलेज एवं टी.डी. कॉलेज परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेते हुए केंद्र व्यवस्थापकध्संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलविहीन आयोजन हम सभी की जिम्मेदारी है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाएं परीक्षा अवधि के दौरान सुचारु रूप से संचालित रहें तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होने पर उसका तत्काल समाध ान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधि कारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा–2026 का आयोजन 02 एवं 03 जुलाई, 2026 को दो–दो पालियों में तथा 04 जुलाई, 2026 को प्रथम पाली में कराया जाएगा। जनपद में परीक्षा के सफल संचालन हेतु कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की सतत एवं प्रभावी निगरानी के लिए 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 23 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 05 आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 08 आरक्षित स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं शासन के दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 से 23 अगस्त को

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सिविल जज सी0डि0ध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार शशि, व सिविल जज सी0डि0ध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में ऐसे वाद, जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं तथा जिनमें समझौतें की संभावना है, उन्हें आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जायेगा। ''समाधान समारोह–2026'' का उद्देश्य केवल वादों का निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी संबंधों को बनाए रखते हुए त्वरित, सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध कराना भी है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को वर्षो तक न्यायालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा समय एवं धन दोनों की बचत होगी। सचिव ने बताया कि उक्त अभियान के सफल संचालन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से व्यापक स्तर पर बैठकों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं समन्वय गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। न्याय को सरल, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से आमजन तक पहुॅचाने तथा आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशन में ''समाधान समारोह–2026'' के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष लोक अदालत अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के आध ार पर किया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, पात्र छात्र–छात्राओं को मिलेगा निःशुल्क आवास

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने बताया कि जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनु0जाति छात्रावास पीलीकोठी, हुसेनाबाद डोभी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय बालकध्बालिका छात्रावासों में छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध हैं। शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु छात्रावास में प्रवेश हेतु वही छात्र/छात्राए अर्ह होंगे जो कि समाज कल्याण विभाग अथवा कल्याण सेक्टर के अन्य विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखते हो। छात्रावास में प्रवेश हेतु कुल क्षमता का 70 प्रतिशत स्थान अनु0जाति/अनु0जनजाति लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे तथा अवशेष 30 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्रा के लिए आरक्षित होंगे। विकलांग छात्रो को प्रवेश हेतु वरियता प्रदान की जायेगी। छात्रावास में प्रवेश छात्र की योग्यता/उच्च शिक्षा की प्राथमिकता/मूल निवास स्थान की दूरी आदि के आधार पर होगा। सामान्य योग्यता के छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार आर्थिक होगा। छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु वेबसाइड upswdhms-upsdc-gov-in पर ऑनलाईन 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लए मोबाइल नम्बर 8795663154, 9795112861 एवं 8726969979 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

साढ़े सात बजे से रहेगा समय, चलेगा स्कूल चलो अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में भीषण गर्मी और तपती धूप के बाद अब मौसम का मिजाज बदलते ही स्कूलों की रौनक फिर से लौटने वाली है। गर्मी की छुट्टियों के बाद प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय भी एक जुलाई से खुल जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलाए जाएंगे। दूसरी तरफ प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी एक जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र 2026–27 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी। ताकि शत–प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। यह अभियान एक से 15 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के प्राइवेट स्कूल भी एक जुलाई से ही खुल रहे हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के लिए 1.63 करोड़ जारी किए गए हैं। नए शैक्षिक सत्र में शत–प्रतिशत नामांकन करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विकास खंडों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अभियान का उद्देश्य विद्यालय से छूटे हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, ड्रॉपआउट बच्चों का पुनः नामांकन कराना तथा नामांकन को व्यापक

जनभागीदारी का स्वरूप देना है। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि अभियान में ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अभियान के दौरान घर–घर संपर्क, ग्राम व वार्ड स्तर पर सर्वे, विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान की जाएगी। इनका प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। अभियान में प्रभात फेरी, नामांकन रैली, घर–घर संपर्क, अभिभावक बैठकें, ग्राम सभाएं, विद्यालय प्रवेशोत्सव, विशेष नामांकन शिविर तथा अन्य जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना तथा हर परिवार को बच्चों के नियमित विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित करना है।

जफराबाद में मासूम बच्ची हत्याकांड सांसद प्रिया सरोज ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और कठोर कार्रवाई की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर सांसद प्रिया सरोज पीड़ित परिवार के घर पहुंचीं और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की और भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हैं। सांसद प्रिया सरोज ने प्रशासन से मांग की कि इस जघन्य मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो (च्व्ब्ै) अधिनियम सहित सभी संबंधित धाराओं में कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों को शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों के प्रति किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता और हरसंभव सरकारी मदद उपलब्ध कराने की भी मांग की। सांसद ने कहा कि इस कठिन समय में परिवार को न्याय के साथ–साथ हर प्रकार का सहयोग मिलना आवश्यक है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. अवधनाथ पाल, राहुल त्रिपाठी, डॉ. सरफराज खान सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में दोषियों को कठोरतम दंड दिलाने और मामले की निष्पक्ष व त्वरित सुनवाई की मांग की।

उद्योग बंधु बैठक में समस्याओं को लेकर उद्यमियों ने प्रशासन को घेरा

लखनऊ, (संवाददाता)। शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही बुनियादी समस्याएं मंगलवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में एक बार फिर जोरदार ढंग से उठीं। अमौसी, नादरगंज, सरोजनीनगर और तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों ने जलभराव, बदहाल सड़कों, बिजली संबंधी कार्यों में देरी और लंबित प्रकरणों को लेकर प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी। जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान की प्रगति बताई, वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। अमौसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन रजत मेहरा ने अमौसी, नादरगंज और सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्रों में जलनिकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित 40 प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। कुछ मामलों का निस्तारण यूपीसीडा, विद्युत विभाग और एलडीए द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई। यूपीसीडा के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण के लिए तैयार एस्टीमेट मुख्यालय भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा। जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम, यूपीसीडा और एनएचएआई के संयुक्त निरीक्षण के बाद शासन को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अमौसी औद्योगिक क्षेत्र स्थित डीवीके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के आसपास जलभराव को लेकर नगर निगम ने बताया कि मशीनों के माध्यम से लगातार पानी निकाला जा रहा है।

जौनपुर में खेत में लगाए गए अवैध करंट से युवक की मौत, गिरफ्तारी की मांग पर शव उठाने से अड़े ग्रामीण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लाइनबाजार थाना क्षेत्र के परियावा गांव में गुरुवार सुबह खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए कथित अवैध बिजली करंट की चपेट में आने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने खेत मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने का विरोध किया। जानकारी के अनुसार, परियावा गांव निवासी साहबलाल गौतम (40) पुत्र फेरई राम गौतम सुबह शौच के लिए पोखरे की ओर गए थे। रास्ते में गांव के ही एक व्यक्ति

ने अपने बाजरे के खेत को आवारा पशुओं से बचाने के लिए चारों ओर लोहे के तार लगाकर उसमें कथित रूप से बिजली का करंट प्रवाहित कर रखा था। बताया जा रहा है कि करंट प्रवाहित तार टूटकर पास स्थित बगीचे तक पहुंच गया था। इसी दौरान साहबलाल उस तार की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के समय पोखरे की ओर जा रहे अन्य लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही लाइनबाजार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रोशित ग्रामीणों ने खेत मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। शव को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बंद मकान पर थी चोरों की नजर, गुडम्बा पुलिस ने 48 घंटे में किया चोरी का खुलासा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के गुडम्बा थाना क्षेत्र में बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले दो शातिर युवकों को पुलिस ने घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने–चांदी के बड़ी मात्रा में आभूषण, एक कलाई घड़ी तथा नकद सिक्के बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई दिनों से बंद पड़े मकान की रेकी की थी और मौका मिलते ही ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।पुलिस के अनुसार 28 जून 2026 को मोहम्मदपुर खत्री, कल्याणपुर निवासी प्रशांत मणि त्रिपाठी ने गुडम्बा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने–चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए हैं। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से साक्ष्य जुटाए और मुखबिरों को सक्रिय किया। सुरागरसी के दौरान मंगलवार को उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सौरव नेहवाल तथा पुलिस टीम ने कुकरैल जंगल क्षेत्र से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उनकी पहचान मयंक वर्मा (19) निवासी ग्राम भंडार, बड्डूपुर थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी, हाल निवासी मैकाले तिराहा, गुडम्बा तथा अभिषेक यादव (20) निवासी कंचना विहारी मार्ग, कल्याणपुर, गुडम्बा के रूप में हुई।तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के चार सोने की अंगूठियां, एक मंगलसूत्र, दो सोने की चेन, एक हार, दो जोड़ी बालियां, नथ की लड़, दो सुई–धागा, एक लॉकेट, तीन जोड़ी टॉप्स, नाक की कील, नथुनी, नग सहित दो नाक की कील, चांदी की करधनी, हाफ पेटी, आठ पायल, कमर की चेन, बच्चों के दो कड़े, चार बिछिया, एक कलाई घड़ी तथा एक और दो रुपये के कुल 138 रुपये के सिक्के बरामद किए।पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने देखा था कि संबंधित मकान कई दिनों से बंद पड़ा है। इसके बाद दोनों ने मकान की रेकी की और रात के समय ताला तोड़कर घर में रखे जेवर और नकदी चोरी कर ली। आरोपियों ने बताया कि चोरी की नकदी वे खर्च कर चुके थे, जबकि आभूषण बेचने की फिराक में थे।

राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, महंत धर्मदास ने लगाई ये गुहार

लखनऊ, (संवाददाता)। गोरखपुर–फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। उन्होंने ट्रस्ट में भगवान श्रीराम के वंशजों, राम मंदिर आंदोलन के कारसेवकों के परिजनों और आंदोलन से जुड़े लोगों को प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं का विश्वास और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास ने कहा कि श्रीराम मंदिर का प्रबंधन मौजूदा ट्रस्ट के बजाय साधु–संतों को सौंपा जाना चाहिए। ट्रस्ट पैसे का हिसाब–किताब रख सकता है, लेकिन धार्मिक और प्रशासनिक कामकाज संतों के हाथों में ही रहने चाहिए। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, मीडिया में इस बारे में आ रही खबरें अति गंभीर व चिंतनीय है। ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं

जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। चढ़ावा चोरी का मामला पुलिस को भी पहले दिन से पता था। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस रकम बरामद करवाने में मदद कर रही थी। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज से ही हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी अविनाश शुक्ला को गाड़ी में बैठाते कैद हुए हैं। साथ में एक बैग है, जिसमें बरामद रकम बताई जा रही है। हकीकत में पुलिस भी वही कर रही थी, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी कह रहे थे। इसलिए सवालों के जवाब में सिर्फ पुलिस की चुप्पी थी। छह जून को चढ़ावा चोरी का मामला मीडिया में आया था। जब मामले ने तूल पकड़ा और ट्रस्टी सवालों से घिरे, तब एसआईटी गठन की मांग हुई। एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद 23 जून को केस दर्ज किया गया। एफआईआर होने से पहले तक कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। हर किसी का जवाब था।

उत्तर प्रदेश टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेज सर्वे-2025 रिपोर्ट जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन (एलएलएफ) ने टाटा ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेज सर्वे (टीएलपीएस)–2025 रिपोर्ट का विमोचन किया। रिपोर्ट में कक्षा 1 और 2 के शिक्षण–अधिगम व्यवहारों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कक्षा–कक्ष की गुणवत्ता सुधार के लिए साक्ष्य–आध ारित सुझाव दिए गए हैं।रिपोर्ट का विमोचन अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थसारथी सेन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार, समग्र शिक्षा के अधिकारियों, टाटा ट्रस्ट, एलएलएफ, डायट, जिला शिक्षा अधि ाकारियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति में किया गया। यह कार्यक्रम ष्पॉलिसी टू प्रैक्टिस डायलॉगरू ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम प्रैक्टिसेजष् विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा नीति और विद्यालयी शिक्षण के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई।रिपोर्ट के लिए नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच बहराइच, बरेली, मिर्जापुर और रायबरेली के 200 विद्यालयों तथा 200 कक्षाओं का अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण के दौरान कक्षा–कक्ष के वातावरण, पाठ संचालन, समय के उपयोग और शिक्षकों के साक्षात्कार के माध्यम से छह प्रमुख आयामोंकृकक्षा वातावरण, पाठ योजना एवं संचालन,

सील होंगे 122 होटल, गेस्ट हाउस बैंक्वेट हॉल

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए और अग्निशमन विभाग के संयुक्त सर्वे में 122 होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन और बैंक्वेट हॉल में गंभीर खामियां मिली हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मानकों के विपरीत चल रहे इन प्रतिष्ठानों को सील करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को एलडीए के पारिजात सभागार में प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में सर्वे रिपोर्ट रखी गई। यह सर्वे करीब एक महीने पहले दिल्ली के एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद कराया गया था लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गोमतीनगर स्थित होटल रेनेसां में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। स्वीकृत मानचित्र में 16वें तल पर जहां छत दर्शाई गई थी, वहां स्काई बार संचालित हो रहा है। जांच में यह भी पता चला कि होटल प्रबंध ान ने लीज पर मिली ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे अवैध बेसमेंट बना लिया है। सर्वे के दौरान गोमतीनगर के होटल नोवोटेल के बेसमेंट पार्किंग में बेकरी, स्टाफ रूम और लॉन्ड्री चलती मिली। होटल लीनेज में भी नियमों का उल्लंघन मिला।

तीन थानेदार और चार अधिकारी गैरहाजिर, नोटिस

गोरखपुर, (संवाददाता)। सहजनवां तहसील सभागार में सोमवार को एडीएम प्रशासन सहदेव मिश्र की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान गीडा, हरपुर बुदहट और खजनी थाने के प्रभारी अनुपस्थित रहे। वहीं, सीएचसी अधीक्षक सहजनवां व पाली, सहायक चकबंदी अधिकारी व एडीओ सहकारिता पिपरौली भी गैरहाजिर मिले। एडीएम ने सभी को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। एडीएम ने कहा कि मामलों का निस्तारण 10 दिन के भीतर कराने का प्रयास करें। जब मामले लंबित रहेंगे तो आईजीआरएस में तहसील का रैंक भी कम होगा। एडीएम प्रशासन के सामने 47 शिकायत पत्र आए, जिनमें सात का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व 24, पुलिस 10, विकास 4, चकबंदी एक, अन्य एक शिकायत पत्र आए। इस दौरान एसडीएम केशरी नंदन तिवारी, तहसीलदार राकेश कन्नौजिया, बीडीओ सत्यकाम तोमर, ईओ सूर्यकांत सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

गुरबाणी कीर्तन से निहाल हुई संगत

गोरखपुर, (संवाददाता)। सिख समाज के गुरु गोबिंद सिंह के 359वें प्रकाश दिवस पर सोमवार को मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरबाणी कीर्तन से संगत निहाल हुई। लोगों ने अरदास किया। गुरुद्वारा में शाम 7:30 बजे से हजूरी रागी भाई हरप्रीत सिंह की ओर से आरती कर दीवान की गई। इसके बाद हरियाणा से आए मनप्रीत सिंह, कमलजीत कौर व गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी रसपाल सिंह की ओर से गुरबाणी कीर्तन व कथा के माध्यम से साध संगत को निहाल किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनमोहन सिंह ने किया। दीवान की समाप्ति के बाद बच्चों क कार्यक्रम में सरदार देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह चड्ढा, अमरजीत सिंह, अरविंदर सिंह, अमृत पाल सिंह, हरबंस सिंह चटवाल, धनवंत सिंह धन्ने, सुखमीत सिंह, मानवेंद्र सिंह भसीन, सतवंत कौर, कवलजीत कौर, गुरबचन कौर व निश्चल कौर आदि का योगदान रहा।

जेल में जाकर आरोपी छात्र का बयान दर्ज करेगी जांच समिति

गोरखपुर, (संवाददाता)। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विश्वेश्वरैया छात्रावास में बीटेक छात्र पर जानलेवा हमले के मामले की जांच कर रही समिति मंडलीय कारागार जाएगी। वहां आरोपी छात्र का बयान दर्ज करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति मंगलवार आरोपी का बयान दर्ज करने जेल में जा सकती है। बताया जा रहा है कि जांच समिति ने इस मामले में सोमवार को बैठक कर कई बिंदुओं पर विमर्श किया। समिति ने छात्रावास में जाकर कई छात्रों से भी बात की। वहां छात्रों ने दोनों के बीच मनमुटाव की बात कही। घटना की रात ड्यूटी पर तैनात रहे गार्ड से भी समिति ने पूछताछ की और इस बार में जानकारी ली। गार्ड ने बताया कि हमला करने के बाद आरोपी छात्र ने ही आकर उसे बताया था कि उसने अपने रूममेट के सिर पर ईंट से हमला किया है। उसे बचा लो। जांच समिति ने घायल शिवांश के पिता से भी बातचीत कर उनका बयान दर्ज किया। घायल छात्र का बयान भी जल्द ही दर्ज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अधिष्ठाता छात्र मामले और चीफ वार्डन प्रो. जय प्रकाश ने भी हॉस्टल के छात्रों, कर्मचारियों, गार्डों से बात कर घटना के बारे में जानकारी हासिल की। उनसे घायल छात्र के परिजन भी मिले। कुछ छात्रों व कर्मचारियों ने बताया कि कमेंटको लेकर अक्सर दोनों के बीच तनाव बना रहता था। हालांकि, कभी दोनों में से किसी ने लिखित शिकायत नहीं की। इस मामले में घटना सामने आने के बाद ही आरोपी आशीष कुमार को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया था। अब उसके खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में छात्रों और कर्मचारियों का एक धड़ा आरोपी छात्र के पक्ष में भी लामबंद होने लगा है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति के आशीष पर अक्सर जातिगत टिप्पणी की जाती थी। सोमवार को कई कर्मचारियों ने हमलावर छात्र के पक्ष में अधिकारियों के समक्ष तर्क और तथ्य रखे। आरोप है कि घटना की रात भी टिप्पणी किए जाने के बाद उसने हमला किया था। शिवांश के पिता अनुपम पांडेय ने बताया कि शिवांश को जेईई मेन में लगभग 81,000 रैंक मिली थी। वह पढ़ने में शुरू से ही मेधावी है। आरोपी छात्र के बारे में भी बताया जा रहा है कि वह भी पढ़ने में मेधावी है। उसने भी बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी। अच्छी रैंक की वजह से ही दोनों ही छात्रों को सबसे अधिक डिमांड वाले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला था। कार्यवाहक कुलपति प्रो. वीके गिरी ने बताया कि नियम के अन्तर्गत छात्र कल्याण निधि से घायल के इलाज में हो रहे खर्च का भुगतान किया जाएगा।

पुलिस ने एक महीने में 50 बार निगम को लिखी चिट्ठी, फिर भी 22 चौराहों से नहीं हटा अतिक्रमण

वाराणसी, (संवाददाता)। विभागों की आपसी खींचतान और रार में ट्रैफिक का बैंड बज रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर काशी और वरुणा जोन के संबंधित थानों ने नगर निगम को 50 बार पत्र भेजा। अभी तक कोई खास सुधार

नहीं हुआ है। हर महीने नगर निगम को पत्र भेजा जाता है। सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट रोडवेज के आसपास अस्थायी तौर पर अवैध स्टैंड संचालन किया जा रहा है। ऑटो, चार पहिया और डग्गामार बसें संचालित हो रही हैं। इन पर लगाम लगाने में पुलिस, आरटीओ और नगर निगम असफल है। कैंट स्टेशन के आसपास गाहे–बगाहे ठेला, खोमचा वाले सड़क पर अतिक्रमण किए रहते हैं। विशेश्वरगंज, मैदागिन, मलदहिया, पांडेयपुर, अर्दली बाजार, आजमगढ़ मार्ग, भोजूबीर–सिंधोरा मार्ग, शिवपुर रेलवे क्रॉसिंग, गिलट बाजार, कचहरी, सोनारपुरा, भेलूपुर, लंका, सामनेघाट, मुरारी चौक, मंडुवाडीह, पंचकोशी सब्जी मंडी–आशापुर मार्ग, पीलीकोठी, नई सड़क, बेनिया तिराहा, चेतगंज समेत प्रमुख क्षेत्रों में अब भी अतिक्रमण के चलते यातायात का दबाव है। काशी और वरुणा जोन के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क पर कभी निर्माण कार्य तो कभी तार बिछाने की प्रक्रिया के चलते खोदाई होती है। कार्य में लापरवाही और ढिलाई के चलते जो काम दो दिन में होना चाहिए, वह हफ्ते भर खींच जाता है। लहरतारा चौड़ीकरण मार्ग के दौरान मलबा सड़क पर फैलाए रखने के कारण वाहनों की रफ्तार सुस्त हो जाती है। लिहाजा जाम लगता है। यही हाल कचहरी से पुलिस लाइन जाने वाले मार्ग का है। मंडुवाडीह चौराहे पर सड़क निर्माण की वजह से सुबह और शाम जाम लगता है। पुलिस को बिना सूचना दिए कार्यदायी संस्था आधे सड़क पर बैरिकेडिंग कर देती है। मन चाहे जगहों पर कट खोल देती है। संस्था की ओर से कर्मचारी भी तैनात नहीं है, ताकि यातायात सुगमता में राहत हो सके। गाजीपुर रूट की बसों का संचालन अब अगले हफ्ते से चांदपुर कलेक्ट्री फार्म के आसपास से संचालित होगा। जमीन चिह्नित कर ली गई है। एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा ने बताया कि लहरतारा में निजी जमीन पर स्टैंड था, जिसकी जमीन थी, उसने स्टैंड बंद करवा दिया। ऐसे में गाजीपुर रूट की बसों का संचालन अगले हफ्ते से चांदपुर कलेक्ट्री फार्म के आसपास से होगा। निजी जमीन चिह्नित की गई है। यह बसें चांदपुर से बौलिया और फुलवरिया फोरलेन होते हुए आवाजाही करेंगी। बीते एक सप्ताह से मेरे पास अतिक्रमण हटवाने का कार्य मिला है। इस दौरान पुलिस ने मौखिक और लिखित जितने पत्र भेजे हैं। सभी पर कार्रवाई की गई है। प्रतिदिन हमारी टीम कहीं न कहीं से अतिक्रमण हटवाती है ताकि यातायात में दिक्कत न आए। –अमित कुमार, अपर नगर आयुक्त काशी और वरुणा जोन में संबधित थानों की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नगर निगम सहित संबंधित विभागों को पत्र भेजा जाता है। अतिक्रमण हटाने के लिए थाने स्तर से ही कार्रवाई की जाती है।

मस्जिदों को तोड़ने के लिए खुद आगे आए मुस्लिम समाज के लोग, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी

वाराणसी, (संवाददाता)। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत बुधवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कराई। पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे, जबकि ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। कार्रवाई के दौरान 13 स्थानों पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई। इस दौरान मस्जिदों को तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग खुद ही आगे आए। चौड़ीकरण की जद में आने वाली करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और निशारान मस्जिद पर संबंधित मुतवल्लियों ने स्वयं ही ध्वस्तीकरण का काम शुरू कराया। वहीं चौड़ीकरण की जद में आने वाले 54 पुराने मकानों पर जेसीबी मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए मीडिया और आम लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई।

आईजीआरएस रैंकिंग में अयोध्या को मिला प्रदेश में आठवां स्थान, लगातार दूसरी बार टॉप-10 में बनाई जगह

(राजन तिवारी सिटी)

अयोध्या। जनपद अयोध्या ने शासन की महत्वाकांक्षी आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जून 2026 की मासिक रैंकिंग में प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब जनपद ने प्रदेश के टॉप–10 जिलों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।इससे पूर्व जारी रैंकिंग में अयोध्या को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था।वर्ष 2020 के बाद यह पहला अवसर है जब जनपद अयोध्या ने लगातार दो माह तक प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

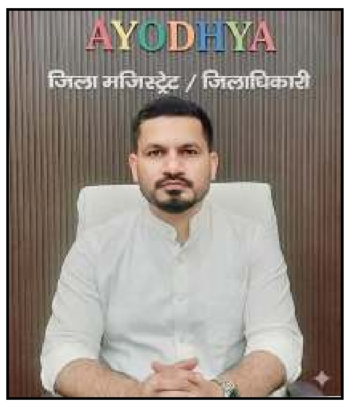

यह उपलब्धि जनपद में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा अधिकारियों की जवाबदेही का सकारात्मक परिणाम है।इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने समस्त जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई की गुणवत्ता बनाए रखते हुए शिकायतों के निस्तारण में निरंतर सुधार करें, ताकि आगामी रैंकिंग में भी जनपद और बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश के शीर्ष स्थानों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सके।

राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर चिकित्सकों को डॉ. बीसी राव अवार्ड से किया गया सम्मानित

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर चिकित्सकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।यह कार्यक्रम सिविल लाइन्स स्थित होटल रेडिसन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अगुवाई आईएमए अध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव एवं सचिव डॉ. निशांत सक्सेना ने की।समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने स्वयं एक डाक्टर होने के नाते आईएमए की सदस्यता ग्रहण की।उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के निस्वार्थ समर्पण, रोगियों के प्रति तत्परता और समाज सेवा को देखकर वे चिकित्सा प्रोफेशन से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. बृजेश सिंह तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार भिटौरिया ने अपने हाथों से चिकित्सकों को डॉ. बीसी राव अवार्ड प्रदान किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. पीएन सिंह को

लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।वहीं डॉ. बी. सी. राव अवार्ड पूर्व डीजी हेल्थ डॉ. रुकुम केश, पूर्व सीएमओ डॉ. नानक सरन, महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विभा कुमारी, डॉ. अतुल वर्मा, डॉ. जे.पी. सिंह, डॉ. आर.वी. वार्षेन सहित को दिया गया। इस अवसर पर डॉ. सी.पी. तिवारी, डॉ सईदा रिजवी, डॉ. एस. के. पाठक, डॉ. वीरेंद्र वर्मा, डॉ. रमेश सिन्हा, डॉ सुनीता सिंह, डॉ. विपिन वर्मा, डॉ. बी.पी. सिंह सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉ. गौरव ग्रोवर ने अपने संबोधन में चिकित्सकों के योगदान की सराहना की।उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स न केवल रोगियों का इलाज करते हैं बल्कि समाज को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के बीच बेहतर तालमेल से आपातकालीन सेवाओं को मजबूत किया जा सकता है।कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी डॉक्टर्स को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

आयुष की अर्धशतकीय पारी से सरमाउंट जीता, फाइनल में प्रवेश

गोरखपुर, (संवाददाता)। स्कूल प्रीमियर लीग के अंतर्गत प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आयुष पांडेय की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सरमाउंट क्रिकेट एकेडमी ने राहुल क्रिकेट एकेडमी पीपीगंज को 66 रन से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली। टॉस जीतकर सरमाउंट क्रिकेट एकेडमी के कप्तान आनंद यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। निर्धारित 20 ओवर में सरमाउंट की टीम ने पांच विकेट खोकर 175 रन बनाए। टीम की ओर से आयुष पांडेय ने छह चौकों की मदद से शानदार 51 रन बनाए। आर्यन सिंह ने 41 रन (पांच चौके, एक छक्का), विवेक यादव ने 39 रन (दो चौके, एक छक्का) और रमेश प्रजापति ने 28 रन (छह चौके) का योगदान दिया। राहुल एकेडमी की ओर से राज यादव ने दो विकेट, जबकि यश मिश्रा और अंकुश यादव ने 1–1 विकेट लिए। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल क्रिकेट एकेडमी पीपीगंज की टीम 17.3 ओवर में 108 रन पर सिमट गई। विवेकानंद यादव ने 55 रन (तीन चौके, छह छक्के) बनाए जबकि यश मिश्रा ने 21 रन जोड़े। सरमाउंट की गेंदबाजी में सन्नी तिवारी ने तीन विकेट, अरसद अंसारी और आरव दुबे ने 2–2 विकेट हासिल किए। दूसरे सेमीफाइनल में लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी ने एवर बॉन्ड को आठ विकेट से हराया। एवर बॉन्ड की टीम 55 रन पर सिमट गई। लक्ष्य एकेडमी ने 11 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार सरमाउंट के सन्नी तिवारी और लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी के हिमांशु सिंह को दिया गया। अंपायर की भूमिका सूरज कुमार यादव और प्रद्युम्न यादव ने निभाई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत

गोरखपुर, (संवाददाता)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का सोमवार को शहर में जगह–जगह जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जाकर माथा टेका। वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय माधव धाम पहुंच कर प्रांत प्रचारक से मुलाकात की। इस दौरान उनका एयरपोर्ट से लेकर माधवधाम तक जगह–जगह स्वागत हुआ। इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत सबसे पहले एयरपोर्ट पर सांसद, विधायक गण और पार्टी पदाधिकारियों ने किया। महानगर, जिला और क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर अलग–अलग स्थानों पर ढोल नगाड़े, गाजा–बाजा, पुष्प वर्षा के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। एयरपोर्ट से जब प्रदेश अध्यक्ष का काफिला निकला तो पंकज चौधरी ने गुरुंग चौराहा पर गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय और रेलवे स्टेशन के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महानगर के 51 स्थानों पर उनका स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। स्वागत करने वालों में सांसद रवि किशन शुक्ल, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, एमएलससी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जर्नादन तिवारी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, राजेश गुप्ता, विश्व जितांशू सिंह, डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, रमेश सिंह, राहुल श्रीवास्तव, डॉ. बच्चा पांडेय व अच्युतानंद शाही आदि उपस्थित रहे।

सड़क व नाला निर्माण बना नासूर, नाका में जाम से कराह रही जनता

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। अग्रसेन चौक से नाका हनुमानगढ़ी तक इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़क व नाला निर्माण के चलते 'सड़क को वन–वे किया गया है, लेकिन सड़क किनारे अवैध पार्किंग, ठेलों और अतिक्रमण ने हालात और बदतर कर दिए हैं।ऊपर से नाका क्षेत्र में चल रही प्रदर्शनी ने कोढ़ में खाज का काम कर दिया है। दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है।सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य की गति धीमी है और प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन के अभाव में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 'कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात नियंत्रित करने के बजाय मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आते हैं जिससे जाम और विकराल हो जाता है।व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए तथा प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए अलग यातायात योजना लागू की जाए, ताकि आमजन को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके।

विधायक के प्रस्ताव पर 17 सड़क व नाली निर्माण को मंजूरी

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत अयोध्या सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के प्रस्ताव पर नगर निगम क्षेत्र में 17 सड़क एवं नाली निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है।इन परियोजनाओं पर 5.46 करोड़ रुपये (546 लाख रुपये) खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था।स्वीकृत परियोजनाओं के तहत नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कराया जाएगा। इसमें अंबेडकर नगर वार्ड के तारापुर रजौली और ककरही बाजार, कर्पूरी ठाकुर वार्ड के सुबेदार का पुरवा, कृष्णा नगर वार्ड के पटेलिया सहबदी, लाला लाजपत नगर वार्ड के आदित्य नगर और मझवा, श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड के विकास पुरम, चित्रगुप्त नगर वार्ड के उसरू, अशोक सिंघल वार्ड के तुलसीबाड़ी, राम मनोहर लोहिया वार्ड के सोलापुरी, झलकारी बाई वार्ड के कुशमाहा, चन्द्रगुप्त नगर वार्ड वजीरगंज, महात्मा गांधी वार्ड के बहाराज बेनीगंज तथा पंडित दीनदयाल वार्ड समेत विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं। इन 17 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 4085 मीटर लंबाई में सड़क एवं नाली निर्माण कराया जाएगा।जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन और जलभराव की समस्या से राहत मिल सके।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या के प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत 17 परियोजनाओं से लोगों को बेहतर आवागमन और जलनिकासी की सुविधा मिलेगी तथा जलनिकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने पदक विजेता स्केटिंग खिलाड़ियों को किया सम्मानित

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने प्रथम ओपन उत्तर प्रदेश राज्य स्पीड स्केटिंग चौंपियनशिप 2026, कानपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद अयोध्या का नाम रोशन करने वाले स्केटिंग खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा खेलों में निरंतर उत्कृ

ष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिता में उत्सर्ग श्रीवास्तव ने 2 स्वर्ण पदक,असीम यादव ने कांस्य पदक,विराज प्रियदर्शी ने कांस्य पदक, शिवान्या सिंह पटेल ने कांस्य पदक,सक्षम पटेल ने कांस्य पदक तथा संस्कार पजवानी ने कांस्य पदक जीतकर जनपद का गौरव बढ़ाया।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर योगानंद पांडे, प्रशिक्षक रविंदर कुमार, वीरेंद्र कुमार एवं अमरेश भी उपस्थित रहे।

दानपात्र राशि गबन मामले में एसआईटी की जांच तेज, लवकुश मिश्र के घर पहुंची पुलिस टीम

(डाक्टर अजय तिवारी जिला रिपोर्टर)

अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से चंदे की राशि में हेराफेरी के मामले में जांच कर रही एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार दोपहर एसआईटी के साथ अयोध्या पुलिस एवं रुदौली कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम लवकुश मिश्र के आवास पर पहुंची।पुलिस टीम ने घर पर मौजूद परिजनों से लवकुश मिश्र के आय के स्रोत, उनके द्वारा खरीदी गई भूमि तथा अन्य कीमती संपत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई। टीम ने काफी देर तक पूछताछ कर मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी एकत्र की।साथ ही भूसे के ढेर आदि में खोजबीन भी की।गांव में एक साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के पहुंचने से लोगों में कौतूहल का माहौल रहा और कार्रवाई को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं होती रहीं।बताया जा रहा है कि दानपात्र से चंदे की राशि में कथित गबन के मामले में एसआईटी विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इसी कड़ी में संबंधित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारियों की ओर से इस कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।